जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 48 संख्याः 94 प्रभात बीकानेर, बुधवार 21 अक्टूबर, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

छात्र आंदोलन का असर सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने की भारत की कोशिशों पर भी पड़ेगा

सरकार द्वारा आंदोलन से निपटने के तरीके से लोकतंत्र के संबंध में भारत के दावे कमज़ोर पड़ रहे हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए छात्र प्रदर्शनों से निपटने के भारत के तरीके ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे समय में, जब भारत वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान बनाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (युनाइटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउन्सिल-यूएनएससी) में स्थायी सीट पाने की कोशिश कर रहा है, इस घटना ने नई दिल्ली की छवि के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है।

"द गार्डियन", "रॉयटर्स", "एसोसिएटेड प्रेस" (एपी) और "अल जज़ीरा" जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्टों और टिप्पणियों में कुई मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया है। इनमें पुलिस द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेना, पत्रकारों पर हमले, प्रदर्शनों पर पाबंदियां और मतदाता सूची में संशोधन से जुड़े विवाद शामिल हैं।

इस कवरेज ने नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के मामले में भारत के घरेलू रिकॉर्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केन्द्र में ला दिया है। भारत अक्सर वैश्विक शासन में बड़ी भूमिका के अपने दावे को मजबूत करने के लिए खुद को "दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र" बताता है। ऐसे में, ये घटनाएं भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और उसके घरेलू संस्थानों के कामकाज के बीच के संबंध पर सवाल खड़े करती हैं।

- प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों, जैसे एसोसिएटेड प्रैस, गार्जियन, रॉयटर्स व अल जज़ीरा ने भारत के इस छात्र आंदोलन को व्यापक कवरेज दी है।
- इस कवरेज में पुलिस द्वारा पत्रकारों व छात्रों को पकड़ने, उन्हें पीटने तथा एसआईआर के मुद्दे को प्रमुखता दी गई है।
- भारत, यूएन में बड़ी भूमिका के लिए हमेशा यह दावा करता रहा है कि वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन, छात्र आंदोलन से डील करने के तरीकों से सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था होने का भारत का यह दावा कमज़ोर पड़ा है।

सबसे तीखी आलोचना "द गार्डियन" की ओर से आई है। अखबार ने 12 अक्टूबर के अपने संपादकीय में तर्क दिया कि सरकार की प्रतिक्रिया से लोकतांत्रिक संकट और गहरा हो सकता है। अखबार ने इस कार्रवाई को चुनाव की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता से जुड़ी व्यापक चिंताओं से जोड़ते हुए कहा कि सरकार केवल प्रदर्शनों को दबाकर लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़े सवालों का समाधान नहीं कर सकती।

वहीं, "रॉयटर्स" और एपी ने उन आरोपों को प्रमुखता से उठाया, जिनमें कहा गया है कि प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों को हिरासत में लिया गया और उन्हें पीटा गया। उनकी रिपोर्टों में, प्रेस द्वारा पुलिस के कामकाज की निगरानी की क्षमता तथा राजनीतिक रूप से संवेदनशील घटनाओं पर स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट कर सकने की क्षमता पर चिंता जताई गई।

"अल जज़ीरा" ने राष्ट्रीय राजधानी में लगाई गई सुरक्षा पाबंदियों पर ध्यान केन्द्रित किया। इनमें परिवहन और इंटरनेट सेवाओं में रुकावटें, और प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया जाना शामिल है। अपनी कवरेज में उन्होंने इन प्रदर्शनों को मतदाता सूची में संशोधन से जुड़े विवाद और युवा भारतीयों की शिकायतों के व्यापक संदर्भ में देखा।

हालांकि इन मीडिया संस्थानों के दृष्टिकोण अलग-अलग थे, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग में एक बात समान थी: क्या प्रशासन द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर दी गई दलीलों के अनुपात में उनकी प्रतिक्रिया उचित थी? और क्या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिग्विजय सिंह ने "सत्य सनातन स्वाभिमान" यात्रा शुरु की

उज्जैन, 20 अक्टूबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' मंगलवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से शुरू हो गई है। करीब 950 किमी की यह यात्रा लगभग 70 दिन में अयोध्या के श्रीराम मंदिर पहुंचेगी।

विजयादशमी के अवसर पर यात्रा के शुभारंभ से पहले, दिग्विजय सिंह ने

- उज्जैन से शुरु हुई यात्रा 950 किलोमीटर चल कर 70 दिन में अयोध्या पहुँचेगी।

अपनी पत्नी अमृता राय के साथ चिंतामन गणेश के दर्शन किए। इसके बाद वे बालाजी गार्डन में पार्थिव शिवलिंग बनाने पहुंचे और यहां शिवलिंग का पूजन किया। यहां पर बड़ी संख्या में संत समाज एकत्रित था। बालाजी गार्डन में उपस्थित जन समहू ने शिवलिंग का निर्माण किया, इस दौरान राम और शिव धुन के भजन के साथ लोगों ने पूजन-अर्चन किया।

बालाजी गार्डन में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी आयोजन की देखरेख में लगे रहे। कन्या पूजन और भोजन प्रसादी समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान में भाग के बाद दिग्विजय ने करीब सवा एक बजे यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में आगे शिव पार्वती की झांकी एलईडी वेन, डीजे, भजन मण्डली, बेंड दल, राष्ट्रीय ध्वज, धर्म ध्वज, ढोल, साधु-संत का करवा शामिल है।

यूसुफ पठान को तृणमूल से बगावत का तोहफा मिला

गुजरात सरकार ने उन्हें वडोदरा में उनके घर के पास का वह भूखंड मात्र आधी कीमत में दे दिया है, जिसे वे 2012 से मांग रहे थे

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान के राजनीतिक निष्ठा बदलने के कुछ ही महीनों बाद गुजरात सरकार ने उन्हें एक तोहफा दिया है। वडोदरा में पठान परिवार के घर के पास स्थित जमीन का एक टुकड़ा अब आखिरकार उन्हें मिल जाएगा। यूसुफ पठान 2012 से इस जमीन को हासिल करना चाहते थे और इसके लिए लंबी कानूनी तथा प्रशासनिक लड़ाई भी चली थी।

इस साल जून में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद, यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के उन 20 सांसदों में शामिल थे, जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की और कम चर्चित एनसीपीआई में शामिल होकर संसद में एनडीए का साथ दिया। पठान 2024 में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में बहरामपुर लोकसभा सीट पर विजयी हुए थे।

विवादित जमीन लगभग 1,000 वर्ग मीटर में फैली है और वडोदरा के तांडलजा इलाके में पठान परिवार के घर के पास स्थित है। उन्होंने, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर होने के कारण सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए, 2012 में

- ज्ञातव्य है कि 2012 से ही इस जमीन के लिए राज्य सरकार से उनका विवाद चल रहा था, लेकिन तृणमूल छोड़कर एनडीए को समर्थन देने के बाद उन्हें आधी कीमत में जमीन दे दी गई है।

पहली बार इस जमीन पर कब्जा दिए जाने की मांग की थी। यूसुफ और इरफान पठान अपने माता-पिता और परिवार के साथ इसी घर में रहते हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, हाल ही में मंजूर की गई नई व्यवस्था के तहत, इस जमीन के मामले में एक तय समझौता किया गया है। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जमीन की कीमत का आधा हिस्सा उन विशेष कल्याणकारी नीतियों के तहत समायोजित किया जाएगा, जो गुजरात से देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए बनाई गई हैं।

इसका मतलब है कि पठान को राज्य सरकार की ओर से तोहफे के रूप में आधी जमीन मुफ्त मिलेगी और उन्हें जमीन की आधी कीमत, यानी 10 करोड़ रु. ही चुकाने होंगे।

अब राज्य के राजस्व विभाग और नगर निगम के विभागों को जमीन हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई है। स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों ने बताया कि आमतौर पर नगर निगम की संपत्तियों की खुली व्यावसायिक नीलामी होती है, लेकिन खेलों को बढ़ावा देने संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत विशेष छूट देकर इस तरह का सीधा समझौता किया जा सकता है।

पठान ने 2012 में सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए इस जमीन को 99 साल की लीज पर देने की मांग की थी। शुरुआत में स्थानीय नगर निगम ने आवास की सुरक्षा के उद्देश्य से जमीन हस्तांतरित करने के प्रस्ताव दिए थे। लेकिन बाद में राज्य के उच्च अधिकारियों ने यह कहते हुए इस कदम को मंजूरी नहीं दी कि सार्वजनिक संपत्तियों के लिए पारदर्शी सार्वजनिक बोली जरूरी है।

समय के साथ यह मामला और जटिल होता गया और इस दौरान प्रशासनिक तथा राजनीतिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी के सभी जिलों में सरदार पटेल की जयंती मनाएगी भाजपा

कुर्मी जाति के असंतुष्ट मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा ने यह निर्णय किया है

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, भाजपा ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने का फैसला किया है। इसके अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के साथ-साथ, 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुर्मी समुदाय तक पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी।

पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में होने वाले इन कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय एकीकरण और आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका को

- सरदार पटेल, जो गुजरात के लेऊवा पाटीदार समुदाय से आते हैं, यूपी के कुर्मी समुदाय में बेहद सम्मानीय माने जाते हैं।
- यूपी में कुर्मी जाति का प्रभाव 48 से 50 सीटों पर है, इसलिए भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है।

उजागर किया जाएगा। पार्टी नेताओं की योजना है कि वे भारत के लौह पुरुष को उचित सम्मान न देने के लिए कांग्रेस की आलोचना करें और इसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' बनाने के फैसले से करें। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसने राजनीतिक कारणों से पटेल के योगदान को कम करके दिखाया है, जबकि मोदी सरकार ने उनके वैश्विक कद को फिर से स्थापित किया है।

सरदार पटेल, जो गुजरात के लेउवा पाटीदार समुदाय से आते थे, उत्तर प्रदेश के कुर्मी समुदाय के बीच बहुत सम्मानित हैं। कुर्मी एक प्रभावशाली खेतिहर ओबीसी समुदाय है तथा राज्य की कुल आबादी में इनकी भागीदारी 5-7 प्रतिशत है। पूर्वांचल, अवध, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पटाखा मुक्त दिवाली के लिए पूरे देश में अभियान

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। दिवाली पर वायु प्रदूषण कम करने और पर्यावरण अनुकूल उत्सव को बढ़ावा देने के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया ने देशव्यापी हरित दिवाली अभियान शुरू किया है। यह अभियान 20 अक्टूबर से 8 नवंबर

- डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया यह अभियान 20 अक्टूबर से 8 नवम्बर तक चलायेगी।

तक चलेगा। इसके तहत लोगों से पटाखे नहीं जलाने, दीये और ऊर्जा दक्ष रोशनी अपनाने तथा कचरे का उचित निपटान करने की अपील की गई है।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया के कार्यक्रम केन्द्र और संसाधन भागीदार ने यह पहल शुरू की है। अभियान के तहत, स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिणक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रियंका गांधी करेंगी, अखिलेश के साथ सीट शेयरिंग वार्ता

पार्टी के अतरंग सूत्रों ने बताया कि नवम्बर तक सीटों के बंटवारे को फाइनल कर लिया जाएगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में 125 सीटें हासिल करने की कोशिश कर रही है।

समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत शुरू करने के उद्देश्य से, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ सीटों के बँटवारे को लेकर तीन घंटे लंबी बैठक की। बैठक में लगभग 175 सीटों पर चर्चा हुई।

कांग्रेस ने करीब 100 'श्रेणी ए' सीटों, 40 से 50 'श्रेणी बी' सीटों और 25 से 35 'श्रेणी सी' सीटों की सूची तैयार की है।

प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के बीच इस सप्ताह एक और बैठक होनी है। इसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी को लगभग 125 से 150 सीटों की सूची सौंप सकती है।

- इस बार, कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव के डेटा के आधार पर सीटों की लिस्ट तैयार की गई है। इनमें से 100 सीटों को "ए" श्रेणी में रखा गया है। 40 से 50 को "बी" श्रेणी में और 25 से 55 को "सी" श्रेणी में।
- कांग्रेस अमेठी, सहारनपुर व रायबरेली की विधानसभा सीटों पर भी दावा कर रही है, जहाँ अभी सपा के विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सीटों पर भी दावा किया गया है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इस कवायद का उद्देश्य नवंबर तक सीटों के बँटवारे को अंतिम रूप दे देना है।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ सीटों के बँटवारे की बातचीत में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका होगी। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस के असफल चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था। उस समय कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और केवल दो सीटें जीत पाई थी।

इस बार, कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनावों और 2017 के विधानसभा चुनावों के आँकड़ों के आधार पर अपनी सीटों की सूची तैयार कर रही है। पार्टी का लक्ष्य हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ना है।

2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इन चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन में अप्रत्याशित सुधार हुआ और उसने कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से छह पर जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 38 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही और 42 अन्य क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही। इन सभी 80 सीटों को पार्टी की इच्छित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)